

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 470
उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

उन्नत उद्यमिता-कौशल विकास कार्यक्रम

470. डॉ. भोला सिंह:
श्री लुम्बा राम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री दर्शन सिंह चौधरी:
श्री खगेन मुर्मू:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) रायपुर आईआईएम सहित विभिन्न आईआईएम के बीच उन्नत उद्यमिता-कौशल विकास कार्यक्रम और प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग से मंत्रालय का कौन-से विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने का विचार है;
- (ख) देशभर में क्रियान्वित किए जा रहे उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी) और प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये निःशुल्क कार्यक्रम महत्वाकांक्षी/उभरते उद्यमियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण एमएसएमई सहित वंचित समुदायों/कमजोर वर्गों के एमएसएमई मालिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और उन्हें लाभान्वित करें;
- (घ) क्या इन कार्यक्रमों को एमएसएमई की वृद्धि और विकास पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए मौजूदा एमएसएमई विकास पहलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार देश में महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्र में एमएसएमई विकास के लिए इन कार्यक्रमों को एकीकृत करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) होशंगाबाद नरसिंहपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) को स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता संस्कृति का विकास करना है।

ईएसडीपी नीति के दिनांक 25.03.2022 दिशानिर्देशों द्वारा, ईएसडीपी स्कीम में उन्नत घटक जोड़े गए थे, ताकि प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईएम रायपुर सहित आईआईएम, आईआईटी, आईसीएआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ, एनआईटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), फसलोत्तर और खाद्य प्रसंस्करण संस्थानों तथा इंजीनियरिंग संस्थानों के माध्यम से ई-कॉमर्स, बीपीओ, सॉफ्टवेयर, बायोटेक, आधुनिक कृषि एवं पशुपालन और प्रसंस्करण, ड्रग डिस्कवरी, जीनोमिक्स और तकनीक अधिग्रहण जैसे विषयों में समग्र/उन्नत प्रशिक्षण प्रदान कर उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्नत उद्यमिता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

ये कार्यक्रम उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने, व्यापार की सतत क्षमता में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य व्यवसाय प्रतिस्थापना, विकास रणनीतियां, वित्तीय प्रबंधन और बाजार विस्तार पर योजनाबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे एमएसएमई के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम को बढ़ावा मिल सके।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, आईआईएम रायपुर को आवंटित कार्यक्रम:

इच्छुक उद्यमियों को व्यवसाय विचार, सत्यापन और निष्पादन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए "नए उद्यम सृजन" पर एक **उन्नत ई-एसडीपी कार्यक्रम**।

"एमएसएमई के लिए व्यवसाय विस्तार" पर एक **उन्नत एमडीपी कार्यक्रम**, जिससे मौजूदा एमएसएमई स्वामियों को विकास रणनीतियां विकसित करने, वित्तीय योजना तैयार करने और बाजार विस्तार में मदद मिलेगी।

(ख) : ईएसडीपी योजना के तहत देश भर में कार्यान्वित उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का उद्देश्य व्यावहारिक अभ्यास, प्रदर्शन और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से भावी और मौजूदा उद्यमियों के कौशल को बढ़ाना है, साथ ही उत्पादकता, लाभप्रदता और उद्यम विकास में सुधार के लिए उन्हें आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों से सुसज्जित करना है।

महाराष्ट्र सहित, पूरे भारत में ईएसडीपी और एमडीपी कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** में उपलब्ध है।

(ग) : मंत्रालय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करके, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा कमजोर वर्गों के उद्यमियों और एमएसएमई स्वामियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग कर उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए स्थानीय संस्थानों और उद्योग संघों के समन्वय के साथ एमएसएमई-विकास कार्यालयों (एमएसएमई-डीएफओ), प्रौद्योगिकी केंद्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता संवर्धन द्वारा ईएसडीपी के तहत इन मुफ्त कार्यक्रमों की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करता है।

(घ) : वर्तमान में ईएसडीपी योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.) : मंत्रालय ने पालघर जिले सहित पूरे महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में ईएसडीपी योजना के तहत, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2022-23 से लेकर अभी तक पिछले 3 वर्षों में पालघर जिले में कुल 38 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 1,663 लोग लाभान्वित हुए हैं।

(च) : उद्यम पोर्टल पर होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में क्रमशः 66,304 और 51,128 एमएसएमई पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने मौजूदा और संभावित उद्यमियों के कौशल विकास संबंधी लाभ हेतु मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में ईएसडीपी योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। होशंगाबाद जिले में 1,882 व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले कुल 40 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जबकि पिछले तीन वर्षों में दिनांक 03.02.2025 तक नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2022-23 से लेकर आज तक 2,559 व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले 58 कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

अनुबंध

दिनांक 03.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक पिछले 3 वर्षों का ईएसडीपी और एमडीपी कार्यक्रमों का महाराष्ट्र सहित अखिल भारतीय विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल कार्यक्रम	कुल लाभार्थी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	28	760
2	आंध्र प्रदेश	108	2795
3	अरुणाचल प्रदेश	68	1772
4	असम	461	11848
5	बिहार	231	6138
6	चंडीगढ़	6	150
7	छत्तीसगढ़	107	2820
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12	305
9	दिल्ली	92	2394
10	गोवा	30	753
11	गुजरात	331	8951
12	हरियाणा	132	3426
13	हिमाचल प्रदेश	68	1707
14	जम्मू और कश्मीर	353	8964
15	झारखंड	135	3655
16	कर्नाटक	230	6835
17	केरल	154	4351
18	लद्दाख*	0	0
19	लक्षद्वीप	8	210
20	मध्य प्रदेश	1472	38463
21	महाराष्ट्र*	513	13235
22	मणिपुर	72	1813
23	मेघालय	72	1854
24	मिजोरम	28	743
25	नागालैंड	637	16426
26	ओडिशा	283	7651
27	पुडुचेरी	22	665
28	पंजाब	208	5307
29	राजस्थान	341	9521
30	सिक्किम	23	583
31	तमिलनाडु	382	10409
32	तेलंगाना	350	9098
33	त्रिपुरा	92	2360
34	उत्तर प्रदेश	460	12252
35	उत्तराखंड	244	6381
36	पश्चिम बंगाल	249	6596
कुल		8002	211191

*लद्दाख में कुल 11 ईएपी (उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम) आयोजित किए गए।